font>

Title: Need to accept the demands of Sarkari Karmachari Rashtriya Parisangh.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी राट्रीय परिसंघ ने जो भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्धित है, जिसमें रेलवे, डाक तार और टेलीकाम विभाग के कर्मचारी भी आते हैं, उन्होंने पिछले 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने एवम् प्रदर्शन किए। अभी 12 दिसम्बर को पांच हजार सरकारी कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर गिरफ्तारियां भी दीं। भारत के प्रधान मंत्री को अपनी मांगों के सम्बन्ध में उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। यह कर्मचारियों से सम्बन्धित मामला है। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर 6 अगस्त, 2003 को तमिलनाडू के कर्मचारियों से सम्बन्धित एक मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। इस सम्बन्ध में अगर संविधान संशोधन भी करने की जरूरत पड़े तो सरकार को वह भी करना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार को बहाल करने की जरूरत है।

इसके अलावा पंचम वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि छठे वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2003 तक कर देना चाहिए। लेकिन उस सम्बन्ध में अभी तक केन्द्र सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पंचम वेतन आयोग ने यह भी कहा था कि अगर महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाए तो उसका मूल वेतन में विलय कर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय 59 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो गया है इसलिए 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समाहित किया जाए। इसके अलावा केन्द्र सरकार द्वारा जो नई पेंशन योजना की घोाणा की गई है, उसको वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना को ही जारी रखा जाए।

भारतीय मजदूर संघ ने भारत सरकार से गत बजट सत्र में आयकर की सीमा एक लाख रुपए तक करने की मांग की थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए आने वाले बजट सत्र में इस मांग को पूरा किया जाए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी आप जानते हैं कि इतना लम्बा भााण नहीं दे सकते, केवल आपको पाइंट बताने हैं। आप जानते हैं कि यहां के रूल्स क्या हैं।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I associate with him. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Your name will be associated with him.

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the Government should bring a legislation to amend the Constitution. ...(*Interruptions*) Right to work is a fundamental right. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Now, Shri Haribhau Shankar Mahale.

â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब माननीय सदस्य शांति से बैठेंगे तो आप सभी लोगों को मौका दे दूंगा।